

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

भारतीय बस्ती

बस्ती 11 मई 2025 रविवार

सम्पादकीय

पाक की बौखलाहट

भारत—पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है और यदि विश्व स्तर पर कोई पहल न हुई तो स्थितियां घोषित युद्ध की ओर जा सकती हैं। दशकों से पाक पोषित आतंकवादियों के हमले झेल रहे भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर व पाकिस्तान में सधे-सटीक मिसाइल हमले करके आतंक का पाठशालाएं ध्वस्त कर दीं। 'ऑपरेशन सिंदूर' से बौखलाए पाक ने भारत के एक दर्जन से अधिक शहरों पर जो जवाबी हमले किए, भारतीय प्रतिरक्षा तंत्र ने उन्हें नाकाम कर दिया। दरअसल, भारत कई मोर्चों पर सीधा चल रहा है। पहलवान हमले के बाद भारत सरकार ने सेना के तीन अंगों के प्रमुखों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व विभिन्न हितधारकों से लगातार संपर्क बनाकर कारण रणनीति की रूप-रेखा बनायी। ताकि पाक के सैन्य प्रतिष्ठानों के नागरिकों को हमले से कोई बड़ा नुकसान न हो। लेकिन भारत की सीमित कार्रवाई को जवाब देने में पाकिस्तान जुलबाजी कर गया। हालांकि, देश के कुछ बड़े शहरों को युद्धक विमानों और ड्रोन के जरिये निशाना बनाने का पाक अभियान हमारी कई परतों वाली सुरक्षा तकनीक से विफल हो गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करके युद्ध की रणनीति पर लगातार विचार करते रहे। इसी तरह सूचना व मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिये पाक को परत किया गया। उसके कई हवाई जहाज व दर्जनों आयातित ड्रोन भारतीय सुरक्षा की परतों को नहीं बंद पाये। वहीं दूसरी ओर, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दुनिया में अपने समकक्षों से संपर्क साध करके आतंकवाद के पोषक पाक को बेनकाब किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो टूक कहा कि वह भारत-पाक संघर्ष के बीच नहीं आएगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाक प्रधानमंत्री से बात कर संघर्ष को विस्तार देने से बचने का आग्रह किया। दरअसल, चीन व तुर्की को छोड़कर दुनिया के तमाम बड़े मुल्क आतंक से प्रभावित भारत के पक्ष में खड़े नजर आए हैं। वहीं सऊदी अरब के उपविदेश मंत्री अदेल अलीजुबैर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघबी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। जिनमें पहलवान हमले के बाद की स्थितियों से अवगत कराया गया। भारत ने आतंक को बढ़ावा देना बंद न करने तक बातचीत से इनकार किया।

मोदी सरकार, सुरक्षा से जुड़े तमाम विभागों तथा सेना के तीनों अंगों ने बेहतर तालमेल के साथ ऑपरेशन सिंदूर तथा उसके बाद पाक द्वारा किए हमलों को विफल बनाने के लिये पर्याप्त होनहार किया। लगातार बैटकों व संवाद के जरिये इस दुनेती के मुकाबले की रणनीति को अंजाम दिया। जिससे देश के जनमानस का भरोसा बढ़ा कि देश सही हाथों में है। अब तक भारत पाक पोषित आतंकवादी हमलों के बाद सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर कार्यवाही की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति मुंबई हमले, संसद पर हुए हमले तथा पठानकोट एयर बेस पर हुए हमलों के बाद सामने आई। भारत सबूतों के आधार पर वैश्विक संगठनों से कार्रवाई की मांग करता रहा है। लेकिन पहलवान हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना नये भारत की बदली रणनीति का पर्याय ही है। पहले पाक के परमाणु हथियार का डर दिखाकर भारत को कार्रवाई करने से रोका जाता रहा है। कालांतर में 2016 में उरी में 19 सैनिकों के मारे जाने पर नियंत्रण रेखा के पार व 2019 में पुलवामा विस्फोट के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। इसी तरह पहलवान हमले के बाद सीधी कार्रवाई करके साफ संदेश दिया कि किसी भी आतंकी हमले का जवाब आतंकवाद को सींचने वाले पाक पर भारत सीधी कार्रवाई करेगा। भारत ने पहले पूरी दुनिया को पुलवामा हमले की साजिश के सबूत दिए और फिर कार्रवाई की। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश भारत के पक्ष में खड़े नजर आए। अब भारत ने महज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाना बंद कर दिया है। निश्चय ही यह रणनीति मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के बजाय अमेरिका व इस्राइल की तर्ज पर घर में सुसुकर मारने की रणनीति है। बहरहाल, भारत ने दुनिया को बता दिया कि पाक अपनी जमीन पर आतंकियों को प्रशिक्षण व समर्थन तो देता है लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाई से बचता है। वहीं दूसरी ओर भारत ने परंपरागत युद्ध शैली से हटकर नई तकनीकों का भरपूर उपयोग किया। भारतीय रक्षा कवच एस-400 यानी सुदर्शन चक्र आदि का पाक हमलों को विफल करना नवीनतम तकनीकों का ही प्रतिफल है।

मुस्लिम देशों में भी अलग—थलग पड़ता पाकिस्तान



—पुष्परंजन—

चांड के राजनयिक हिस्से ग्राहम ताहा, 57 देशों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के 12वें महासचिव हैं। 17 नवम्बर, 2021 से वो इस पद को सम्हाल रहे हैं। ताहा, तुर्किये के राष्ट्रपति रिजप तैय्यप एर्दोघान के 'यस मैं' माने जाते हैं। ताहा की आत्मा, तुर्की और दर्दनाम में बसी रहती है। वर्ष 1969 में अपनी स्थापना के बाद से तुर्की, इस्लामिक सहयोग संगठन में एक प्रमुख खिलाड़ी की भूमिका में रहा है। ओआईसी के कई सारे सदस्य मानते हैं, कि तुर्की इस मंच का दुरुपयोग कर रहा है। 'न्यायिक' से जारी अपने बयान में, ओआईसी ने दोनों पक्षों के बीच मारनेवाली को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार शक्तिपूर्ण तरीकों से हल करने का भी आह्वान किया। लेकिन, भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा, कि यह दो देशों के बीच का मामला है, इसमें आपकी नवीनतम की जरूरत नहीं।

पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखकर पर्दाशन जो दाब चल रहे हैं, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है।



विगत 56 वर्षों से शाह-मात का यह खेल चल रहा है। वर्ष 1969 में मारक्को के किंग हसन द्वितीय ने खात में 1969 के शिखर सम्मेलन के लिए भारत सरकार को आमंत्रित किया। लेकिन, पाकिस्तान के तत्कालीन शासक जनरल यादवा खान द्वारा, बैठक से बाहर निकलने की धमकी दिए जाने के बाद, शाह हसन द्वितीय ने भारतीय प्रतिनिधियों से बैठक में शामिल न होने का अनुरोध किया।

पाकिस्तान, तैहरान में ओआईसी 1994 सम्मेलन के दौरान, सरस्वत देशों को कश्मीर पर ओआईसी संपर्क समूह बनाने के लिए राजी करने में सफल रहा। इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद का 46वां सत्र 1 और 2 मार्च, 2019 को अबू धाबी में आयोजित किया गया था। तब तत्कालीन विदेश मंत्री सुभाष स्वराज को संयुक्त अरब अमीरात के उनमें सम्मेलन केक अब्दुल्ला बिन जयद अल नाययान द्वारा उद्घाटन समारोह को संबोधित करने के लिए

विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तब पाकिस्तान को शाहद मिर्ची लगी।

पाकिस्तान ने भारत द्वारा अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का हवाला देते हुए उसे शिखर सम्मेलन से निष्कासित करने की मांग की। ओआईसी ने पाकिस्तान के अनुरोध पर कश्मीर संपर्क समूह की आपातकालीन बैठक बुलाई, यह बैठक 26 फरवरी, 2019 को हुई। हालांकि, ओआईसी ने भारत द्वारा पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की निंदा की, लेकिन, खुर्द ने भारत को निम्नण भास करने से इनकार कर दिया। सुभाष स्वराज उन सच में पर गयी, और अपने ओजपूर्ण भाषण से पाकिस्तान को एक्सपोज किया। सभी सदस्य इस बात पर सहमत हुए, कि आतंकवाद को बढ़ाया जाना दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक है। ओआईसी के मंच पर यह पाकिस्तान की पहली हार थी।

इरान खान के समय सऊदी अरब से भी ठन गई, जो ओआईसी

का दबंग देश है। जेदा में ओआईसी का मुख्यालय सऊदी खर्च पर ही चल रहा है। अन्य कई पूर्वाग्रहों के अलावा पाकिस्तान, सऊदी से इस बात पर भी खार खोये था, कि कश्मीर मुझे पर खे खलकर उसका सम्मेलन नहीं कर रहा। शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब से तपे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि खालालम्पुर सम्मेलन में जाने से हमें रियायत न रोका था। फाइनलियल टाइम्स अखबार के अनुसार, कुरैशी की टिप्पणियों से सऊदी अरब के अहंकारी भड़क गए, जो ओआईसी के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसने 35.2 बिलियन डॉलर की तेल उन्नत सुविधा को रोक दिया, और पाकिस्तान से 3 बिलियन डॉलर के ऋण का कुछ हिस्सा चुकाने की मांग की। सिर्फ इतने भर से पाकिस्तान की हवा निकल गई। उन दिनों इरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। शाह महमूद कुरैशी ने एक ब्रॉडकास्टर के जरिये बयान

दिया, 'मैं एक बार फिर सम्मानपूर्वक ओआईसी से कह रहा हूँ कि विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक हमारी अपेक्षा है कि कश्मीर पर बैठक बुलाएँ। हमारी अपनी संवेदनशीलताएँ हैं। खाड़ी देशों को यह सम्झना चाहिए।' वर्ष 1994 में कश्मीर पर जो ओआईसी संपर्क समूह बनाया गया था, उसमें सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान और नाइजर शामिल रहे हैं। बाद में सऊदी अरब, नाइजर और अजरबैजान इस मुँहे पर मौन रह गए। संपर्क समूह, ओआईसी सदस्यों के बीच बड़ो सहयोग, कश्मीरी लोगों का तथ्यांकित स्वास्थान और स्वायत्तता को सम्बंधन करने पर जोर देता था। पाकिस्तान प्रशासन की हमेशा यह हठवर्तीता रही है, कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन के अनुसार कश्मीर का मविथ तय किया जाना चाहिए। दसम्बर, 1964, 1972, 1999 और 14 से 16 जुलाई, 2001 तक आहत आगरा शिखर सम्मेलन में भी कश्मीर समस्या का समाधान पकिस्तान ने होने नहीं दिया।

वाशिंगटन स्थित डब्लो विलसन सेंटर फॉर स्कॉलर के दक्षिण एशिया विशेषज्ञ महाल कुलमैन एक ईमेल के जरिये रिपट करते हैं, 'पाकिस्तान के पास वास्तव में कश्मीर पर कोई योजना नहीं है। यह पिछले कई वर्षों से कूटनीतिक अफगण कर रहा है, लेकिन ऐसे देश के लिए विलकुल नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने इस समय से वैश्विक मंच पर कश्मीर मुँहे को अगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इससे एक ख्यामांक प्रश्न उठता है, यदि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक अभियान सफल नहीं होता है, तो इसकी दूसरी योजना क्या है?'—लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

रक्षा तकनीक से लैश ऑपरेशन सिंदूर



—डॉ. शशांक द्विवेदी—

भारतीय संचार बलों द्वारा बीते 6-7 मई की रात को शुरू किया गया 'ऑपरेशन सिंदूर' एक सटीक सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। यह अभियान 22 अग्रेज को जम्मू-कश्मीर के पहलवान में हुए आतंकी हमले के पश्चात में शुरू किया गया, जिसमें 26 पड़ोस मारे गए थे। ऑपरेशन का प्रथमिक उद्देश्य आतंकी संगठनों के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना और भारत में भविष्य के हमलों को रोकना था।

योजना की शुरुआत पहलवान हमले के तुरंत बाद हुई, जब प्र. गामंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल को बुनियादी एजेंसियों और राष्ट्रीय तकनीकी सुरक्षा संगठन के साथ समन्वय करना कि निर्देश दिया। लक्ष्यों की पहचान के लिए सटीकता इमेजरी, मानव बुद्धि का उपयोग और इंटरसेप्टेड संचार को गुप्तयोग किया गया। ऑपरेशन का प्रथमिक और सटीक रणनीति के लिए केवल शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सरकारी नेतृत्व को इसकी जानकारी थी, जब सुनिश्चित किया जाना कि हमले आतंकी ठिकानों तक सीमित रहे।

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना, नौसेना, और वायुसेना ने संयुक्त रूप से काम किया, जो 54 वर्षों में पहली बार इसने बड़े पैमाने पर हुआ। भारतीय वायुसेना ने राफेल और मिगरा 2000 लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जो सटीक हमलों के लिए महत्वपूर्ण थे। बल सेना ने एम77 हेलीकॉप्टर बलों को साथ सहायता प्रदान की, जबकि नौसेना ने समुद्री निगरानी और समर्थन में योगदान दिया। विशेष बलों ने ऑपरेशन से पहले लक्ष्यों की टोह की और हमलों के बाद नुकसान का अंशजकन किया। ऑपरेशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा की गई। जिसमें बताया गया कि नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। बुद्धि एजेंसियों, विशेष रूप से रिसर्च एंजलिसिड विंग (रिव), ने लक्ष्यों का चयन किया, जैसे कि बहावलपुर में जैक-ए-मोहम्मद का मरकत सुभान



अल्लाह और मुजफ्फरबाद में सैयदान बिलास डेव।

ऑपरेशन में अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों का उपयोग किया गया। भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों से स्कैलर जूग मिसाइलें लेंच करके सटीक-निर्देशित बन दाने। स्कैलर मिसाइलें स्टैली तकनीक से लेंच थीं, जो राइल से बचकर कर पड़ोस पर उड़ान मरती है और 450 किलोग्राम वॉरहेड के साथ बंकरों को नष्ट करने में सक्षम हैं। हैनर बलों में जीपीएस और लेजर गाइडेंस सिस्टम था, जो रात और प्रतिबुद्धी मौन में सटीक हमले सुनिश्चित करता है।

मिराज 2000 जेट्स ने स्पार्क 2000 और एमपाइ77 होवित्जर तोपों से एक्सेस सिंवर 155 मिसाइलें-निर्देशित लक्ष्यों लगे गए। आसपासती ड्रोन, जैसे एम्कॉस्ट्राइकर लॉन्गटैंग मुनिशन, ने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट किया। मेटिडोर मिसाइलों ने हवाई सुरक्षा सुनिश्चित की। इन हथियारों ने भारत की सैन्य तकनीक के उन्नत को प्रदर्शित किया, जो 2019 के बालाकोट हमले के तुलना में अधिक सटीक और प्रभावी थी। ड्रोन और सटीकता तकनीक ने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हैरान ड्रोन ने 'रियन-टाइम' निर्देशित और माइक्रो-निर्देशित हमलों में योगदान दिया। स्पार्कस्ट्राइकर जैसे क्राइकेज ड्रोन ने लक्ष्यों पर लंबे समय तक मंत्राकर सटीक हमले किए। सटीकता इमेजरी ने लक्ष्यों की सटीक स्थिति और नुकसान के आकलन में मदद की।

धर्मल इमेजिंग और इन्फ्रारेड इमेजिंग स्ट्रिमट्रॉप सिस्टम ने रात में ऑपरेशन को संचालन बनाया। ड्रोन के 100 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेश किया, जिससे पाकिस्तानी रक्षकों को चकमा देने में मदद मिली। सटीकता इमेजरी ने हमलों के बाद मरकत स्थान अलगाव जैसे ठिकानों के पूर्ण विनाश की पुष्टि की। ऑपरेशन की कमान एनएएफ अजीत डोमाल ने संभाली, जो तीनों सेनाओं के साथ समन्वय में थे। पीएम मोदी ने ऑपरेशन की निगरानी की और अंतिम स्वीकृति दी। एक छोटी, गोपनीय टीम ने लक्ष्यों की निगरानी और सटीक किया। कमांड सेंटर ने रियन-टाइम डेटा और फीडबैक का उपयोग करके हमलों को सिक्राना किया।

विदेश सचिव विक्रम निखी ने 13 देशों के राष्ट्रवादों को ऑपरेशन की जानकारी दी, जिससे भारत की जासनीतिक पारदर्शिता प्रदर्शित हुई। खा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों को साथ समीक्षा की। यह प्रमाणी भारत की सैन्य और कूटनीतिक समन्वय की परिपक्वता को दर्शाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने कई नूतन-निर्देशित और गोपनीय कूटनीतिक का सामना किया। पाकिस्तान की प्रमाणित क्षमता और चीन का समर्थन एक जटिल नूतन-जासनीतिक स्थिति पैदा करता है। भारत ने सटीक और सीमित हमलों के माध्यम से युद्ध की संभावना को कम किया। भौगोलिक रूप से लक्ष्य पाकिस्तान के पड़ोस और पीओके के पहाड़ी क्षेत्रों में थे, जहां रात से सैन्य सटीक हमले बुनीतपूर्व थे।

ऑपरेशन को रात 1:00 बजे शुरू किया गया। सटीक तकनीक, जैसे स्कैलर मिसाइलें और राफेल का समर्थन एक जटिल नूतन-जासनीतिक स्थिति पैदा करता है। भारत ने सटीक और सीमित हमलों के माध्यम से युद्ध की संभावना को कम किया। भौगोलिक रूप से लक्ष्य पाकिस्तान के पड़ोस और पीओके के पहाड़ी क्षेत्रों में थे, जहां रात से सैन्य सटीक हमले बुनीतपूर्व थे।

ऑपरेशन को रात 1:00 बजे शुरू किया गया। सटीक तकनीक, जैसे स्कैलर मिसाइलें और राफेल का समर्थन एक जटिल नूतन-जासनीतिक स्थिति पैदा करता है। भारत ने सटीक और सीमित हमलों के माध्यम से युद्ध की संभावना को कम किया। भौगोलिक रूप से लक्ष्य पाकिस्तान के पड़ोस और पीओके के पहाड़ी क्षेत्रों में थे, जहां रात से सैन्य सटीक हमले बुनीतपूर्व थे।

ऑपरेशन को रात 1:00 बजे शुरू किया गया। सटीक तकनीक, जैसे स्कैलर मिसाइलें और राफेल का समर्थन एक जटिल नूतन-जासनीतिक स्थिति पैदा करता है। भारत ने सटीक और सीमित हमलों के माध्यम से युद्ध की संभावना को कम किया। भौगोलिक रूप से लक्ष्य पाकिस्तान के पड़ोस और पीओके के पहाड़ी क्षेत्रों में थे, जहां रात से सैन्य सटीक हमले बुनीतपूर्व थे।

महंगाई, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी



— डॉ. सत्यवान सौरभ—

जब भी किसी देश में संकट का सामना करता है, सबसे पहले आम जनता पर इसका असर पड़ता है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि संकट के दौर में महंगाई, कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी समस्याएँ आम हो जाती हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के महानुर देभार में खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल और रसायन गैस की कालाबाजारी की खबरें सुर्खियों में हैं। इन मुश्किल हालातों के बीच सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या इन घोषणाओं से वास्तव में कोई फर्क पड़ेगा या फिर यह भी अन्य सरकारों की तरह सिर्फ कागजी सख्ती बनकर रह जायेगी।

इतिहास गवाह है कि जब-जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, तब-तब न केवल सीमावर्ती इलाकों में, बल्कि पूरे देश में खाद्य पदार्थों और ईंधन की किल्लत का माहौल पैदा हुआ है। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। राजनीतिक तान के लिए कई बार जमाखोरी और कालाबाजारी को न केवल नजरअंदाज किया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से प्रोत्साहित भी किया जाता है। सरकारें अक्सर महंगाई और किल्लत को रद्दारीय सुधार के नाम पर सही ठहराती रही हैं। यह एक प्रचलित नीति है कि संकट के समय लोगों को ध्यान भटकाने के लिए देशभक्ति की भावना को उभारा जाता है, लेकिन इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगताना पड़ता है।

सकल द्वारा जारी सख्त निर्देशों के बावजूद, भारतीय स्तर पर इनका क्रियात्मक हमला हो चुका है कई चुनौती रहा है। आमतौर पर, प्रशासनिक अधिकारी इन्हे गंभीरता से नहीं लेते या फिर स्थानीय व्यापारियों और नेताओं के दबाव में आकर मुँद लेते हैं। यह एक खुला राज है कि कालाबाजारी करने वाले अक्सर राजनीतिक संरक्षण में फलते-फूलते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि



क्या सिर्फ आदेश जारी कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या प्रशासनिक नीतियों अपने काम में पर्याप्तता और ईमानदारी के साथ करीबी या फिर यह भी केवल कागजी में बंद होकर रह जाएगा?

जब जमाखोरी होती है, तो इसका सबसे बुरा असर आम जनता पर पड़ता है। महंगाई आसमान छूने लगती है, जरूरी वस्तुएं बाजार से गायब हो जाती हैं, और लोगों को नजदीक में अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। सरकारें महत पैकेज और सख्त रणनीति की योजनाएँ तो बनाती हैं, लेकिन उनका काम जरूरतमंदों तक पहुँचाना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। इसके पीछे केवल भ्रष्टाचार तब इस बुरा कार्ड में सख्त बनकर रह जाएगी। सवाल तो भी सख्त रहना होगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, जब भी सख्ती का रस्ता लगेगा, ताकि कोई जमाखोरी उदामा हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएँ समाप्त नहीं होती, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियाचर्यन से ही सुचारु संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नज़र करना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना,

हे पहात भात-पाक का बीच तनाव और दूसरा भीषण मर्त अथवा विलगिलती झू। पल-पल की खबर लेने के लिए जिलेवासी बेताब रहते हैं। लोग टीवी से चिक्के रहते हैं। बहुत जगहों होने पर दुनो धरों से निकार रहे हैं। इससे अल्पवयव पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। पाक के नापाक हमलों को नापाक करने वाली भारतीय रक्षा शक्ति की सहजाना जिले का हर नागरिक चर रहा है।

वर्तमान में पाक से आयात होने सीने परवृत्ती पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने यह कदम पिछले महीने पहलगान आतंकवादी हमलों के बाद उठाया है। आतंकी नागविक्रिया को समर्थन देने की पुसोरी देती की करवतों के कारण भात और

bhartiyabasti@gmail.com